वैश्विक आतंकवाद का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव : चुनौतियाँ एवं समाधान के उपाय

डॉ0 उमारतन यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र,विभाग,
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय (झाँसी)

शोध सारांश

आतंकवाद किसी देश तक सीमित नहीं है यह लगभग प्रत्येक देश की विकराल समस्या बन गया है। यहाँ तक की पाकिस्तान,अफगानिस्तान,ईराक,इजराइल और लेबनान जैसे देश भी इस समस्या से ग्रस्त है जोकि स्वयं आतंकवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। आतंकवाद के वैश्विक प्रभाव गहन एवं गम्भीर होते हैं जो अन्ततः अर्थ–व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कारगिल युद्ध व 26/11 के पश्चात भारत एवं पाकिस्तान के अन्तराश्ट्रीय सम्बन्धों में और अधिक कड़वाहट बढ़ी, परिणामतः दोनों देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आयी। कृषि उत्पादों के आयात–निर्यात तो लगभग बन्द ही हो गये। चूंकि 26/11 हमलों के शिकार विश्व के कई अन्य देशों के नागरिक, राजनयिक व आर्थिक विशेषज्ञ हुए, परिणामतः आतंकवाद से लड़ने की भारत की तैयारी व क्षमता पर भी सवाल खड़े हुए जिसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आतंक का दीर्घकालीन प्रभाव अमूल्य जीवन व उत्पादन शक्ति का नुकसान तो होता ही है,इसके साथ ही यह बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति की क्षति भी करता है।

Keywords : *वैश्विक आतंकवाद,अर्थव्यवस्था,आंतरिक और वाह्य,खतरे*

आतंकवाद का दुष्प्रभाव न केवल भारतीय परिदृश्य में पड़ा है अपितु यह लगभग पूरी दुनिया को अपनी जहरीले डंकों से ग्रसित कर रहा है। यह माना जा सकता है कि किसी देश में इसकी तीव्रता ज्यादा है तो किसी देश में कम। उदाहरण के लिए इजराइल–जार्डन में फिलीस्तीनी गुरिल्ले, ईराक–ईरान में कुर्द, जापान में रेड आर्मी, लीबिया में अबू–निदाल संगठन, स्पेन में बास्क, श्रीलंका में लिट्टे, जर्मनी में बादर–मीनहोफ तथा फिलीपीन्स में हुकवाला जैसे कई आतंकवादी संगठन अपने ध्वंसात्मक उपायों द्वारा वैशिक परिदृश्य में आतंक का कहर ढा रहे हैं।

आतंकवाद ने समाज में बहुयामी विषमता, असंतुलन, क्षेत्रीय असमान्ताओं को जन्म दिया है। आतंकवाद के कारण ही जातिय एवं वर्णगत वर्चस्ववादिता, धार्मिक असहिष्णुता, अन्धविश्वास, धर्मगत राज्य व कट्टरवादिता को जन्म दिया हैं । शांति प्रिय आम जनता को युद्ध की विभिषिका में झौंका है। आतंकवाद ने एक बीमार सामाजिक व्यवस्था को भी जन्म दिया है। इसकी उत्पत्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मांगों की तरफ एक लम्बे समय तक ध्यान न देने या एकाकीपन के परिणाम स्वरूप होता है। आज की स्थिति में असंतोष, हतासा, निराशा, उपेक्षा,शोषण और अत्याचार इसके प्रमुख कारण हैं। जब तक न्याय मिलने में विलम्ब या कुप्रबंध किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगाए आतंकवाद बढ़ेगा । आतंकवाद ने भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को समाप्त कर दिया है। नैतिक मूल्य दिखाई नहीं

देते। सौहार्द, परोपकार,भाई चारा और सहष्णुता, मानों पुस्तकों में पढाये जाने वाले पाठ बनकर रह गये हैं।

अनेक साक्ष्य इस बात की वकालत करते हैं कि आतंकवाद की जड़ें पहले भी वैश्विक परिदृश्य में सक्रिय थीं और आज भी समूचे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए है। अन्तर इतना है कि आज आतंकवाद का अर्थ एवं परिभाषा बदल गयी हैं। पहले भी मुसोलिनी, जर्मनी का हिटलर, चीन के माओ एवं सोवियत संघ के स्टालिन को आतंकवाद के प्रस्तोता माना जाता था, लेकिन इनकी गतिविधियाँ वर्तमान आतंकवादियों से पूर्णरूपेण अलग थीं। आज की परिभाषा के अनुसार इन्हें आतंकवादी बिल्कुल नहीं माना जा सकता है।

11 सितम्बर सन् 2001 ई0 में अमेरिका पर आतंकवादी हमले ने तो सारे विश्व को भय एवं डर से अचम्भित कर दिया है। (वर्ल्ड ट्रेड टावर और पेंटागन पर हमले)। अमेरिका पर हमले के बाद जम्मू–कश्मीर विधानसभा पर आतंकवादियों के हमले हुए, इसके पश्चात् भारतीय संसद पर दिसम्बर 2001 में हमले हुए, इसी के साथ–साथ आतंकवादियों द्वारा लाल किले में गोलाबारी की गयी, गुजरात राज्य के गाँधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर हमला करके निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला यहीं तक नहीं थमा बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई को अस्त–व्यस्त करने के उद्देश्य से होटल ताज पर आतंकी हमला किया गया। मुम्बई के आतंकी हमले में पाकिस्तान स्थित लश्कर–ए–तैइबा की क्षमताओं को देखने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेन्सियों के अधिकारियों का कहना है कि यह संगठन अब अलकायदा (स्थापना 1988, संस्थापक) प्रमुख – ओसामा बिन लादेन (अमीर), अल जाहिरी (नायब अमीर) से ज्यादा पीछे नहीं है। लश्कर ए ताइबा की स्थापना 1989–90 में अफगानिस्तान के कुनार प्रान्त में की गयी थी। इसके संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद, जफर इकबाल। इसका मुख्यालय पाकिस्तान में लाहौर के पास मुरादेक में। इस आतंकवादी संगठन का उद्देश्य इस्लाम का विस्तार और जम्मू–कश्मीर को भारत के नियंत्रण से मुक्त कराना है। आतंकवाद की चपेट में विश्व के कई देश सम्मिलित हैं। बाली में अमेरिकी दूतावास पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। इसी तरह यमन में अमेरिकी एजेंसी पर हमला किया गया। अमेरिका के चीफ आफ स्टाफ माइक मुलेन ने कहा है कि पहले जम्मू–कश्मीर तक सीमित रहे लश्कर–ए– ताइबा ने अमेरिकयों, ब्रिटिश और यहूदियों को मार कर आतंक की नई दहलीज को पार किया है। इन आतंकवादी हमलों में अब तक न जाने कितने हजारों लोगों, सुरक्षा बलों और पुलिस जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया है, साथ ही साथ संपदा को भारी नुकसान पहुँचा है। भारत को विभिन्न राज्य आमंकवाद की ज्वाला में जल रहे हैं। इन राज्यों में जम्मू–कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस राज्य में सीमापार पाकिस्तान से आतंकवादियों को धन एवं सैन्य सामग्री मुहैया करायी जाती है।

विगत कई दशकों से भारत आंतरिक और वाह्य आतंकवाद से ग्रस्त रहा है। भारत के पड़ोसी देश जिनमें चीन व पाकिस्तान प्रमुख हैं, लगातार भारत में समय–समय पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करते आ रहे हैं। इसकी वजह से एशिया के इन देशों से व्यापारिक गतिविधियां अत्यन्त न्यूनतम स्तर पर रही हैं जिसके कारण भारत समेत इन समस्त राष्ट्रों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी है तथा उनका विकास अवरुद्ध हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों से अच्छे सामरिक सम्बन्धों के अभाव में अनेक अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं कई वर्षों से लम्बित पड़ी हुई हैं जिसमें भारत–ईरान गैस पाइप लाइन परियोजना का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इस परियोजना के समय से पूर्ण नहीं होने से भारत में गैस आपूर्ति की

समस्या अत्यन्त गंभीर होती जा रही है। भारत के अत्यधिक समय तक आतंकवाद से ग्रस्त रहने के कारण न केवल पड़ोसी देशों से वरन् विश्व के अन्य देशों से भी व्यापारिक रिश्ते कमजोर हुए हैं तथा विश्व आयात एवं निर्यात में भारतीय हिस्सेदारी में भी गिरावट दर्ज हुई है। 1948 से 2002 तक की अवधि के बीच विश्व के कुल निर्यात में चीन का हिस्सा 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 6.6 प्रतिशत, जापान का 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 6.6 प्रतिशत तथा भारत का हिस्सा 2.2 प्रतिशत से घटकर 0.8 प्रतिशत तथा अन्य 6 पूर्वी एशियाई देशों का हिस्सा 3 प्रतिशत से बढ़कर 9.6 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान विश्व के कुल आयात में चीन का हिस्सा 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत, जापान का 1 प्रतिशत से बढ़कर 5.2 प्रतिशत, भारत का 3.1 प्रतिशत से घटकर 0.9 प्रतिशत तथा 6 अन्य पूर्वी एशियाई देशों का हिस्सा 3 प्रतिशत से बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गया। उपरोक्त आंकड़ों के आंकलन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि विदेशी व्यापार (आयात एवं निर्यात) के क्षेत्र में 1948 तक भारत की हिस्सेदारी अपने समकक्ष चीन तथा जापान से कहीं अधिक थी परन्तु वर्ष 2000 तक चीन, जापान तथा 6 अन्य पूर्वी एशियाई देशों का योगदान भारत से कहीं अधिक हो गया है। वर्तमान समय में कुल विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से कम है। भारतीय विश्व व्यापार के गिरावट के कई प्रमुख कारण थे जैसे कि पूर्व में भारत का निर्यात चाय, कपास तथा रुई आदि वस्तुएं थीं जिनकी मांग अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार में बेलोचदार थी तथा साथ ही साथ आधुनिक उत्पादन तकनीक के अभाव में अधिक उत्पादन लागत तथा परिणामस्वरूप अधिक कीमत भी भारतीय निर्यात की गिरावट की प्रमुख वजह थी। भारत के विश्व व्यापार में कमी का एक कारण भूमण्डलीकरण तथा विश्व व्यापार संगठन भी रहा है। भूमण्डलीकरण के कारण विश्व व्यापार अधिक सरल हो गया तथा भारत समेत अनेक विकासशील देशों को मात्रात्मक तथा गुणात्मक प्रतिबंध हटाने के लिए विवश होना पड़ा। विश्व व्यापार की शर्तों को अपनाने के पश्चात् भारत विश्व के विकसित तथा कई अधिक विकासशील राष्ट्रों के उत्पादों का बाजार बनकर रह गया है।

लगभग तीन दशक से आतंकवाद का दंश झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। जो खर्चा भारत के आर्थिक विकास , निर्माण ,रोजगार और विनियोग पर खर्च होना था वह पैसा आतंकवाद को खत्म करने की दिशाओं में लगाया जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा ध्यान इन जिहादी आतंकवादी घटनाओं को समझने और उसे समाप्त करने की दिशा में लगा है। आज भारत का आर्थिक विकास जैसे थम सा गया है । भीषण बेरोजगारी, जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए रोटी, कपडा, और मकान की व्यवस्था नई सदी के भारत का स्वप्न मानो एक स्वप्न सा बन कर रह गया है।

आतंकवाद समाप्ति के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

आतंकवाद के निवारण तथा उसे दण्डित करने के उद्देश्य से विश्व के सभी देश प्रायः एक जुट होकर इससे निपटने के उपाय खोज रहें है। कुछ महत्वपूर्ण समझौते इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील हैं–एक नवम्बर से 16 नवम्बर 1937 ई0 में जिनेवा में आतंकवाद के निवारण के लिये एक कान्सप्रेस हुई । और आतंकवाद से निपटने का चार्टर तैयार हुआ ।

अमेरिका राज्यों के संगठन ओ.ए.एस. की महासभा ने 25 जनवरी से 2 फरवरी 1971 तक वाशिंगटन में आयोजित अपने अधिवेशन में 6 अन्तर्राष्ट्री महत्व वाले आतंकवादी कृत्यों के निवारण और उन्हें दंडित करने के लिये कन्वेंशन को स्वीकृति दी । आतंकवाद को समाप्त के लिए 1977 में स्ट्रासवोर्ग में यूरोपीय कन्वेंशन हुई । आतंकवाद के मासले तथा आतंक को रोकने की दिशा में 7 सितम्बर 2001 को भारत फ्रांस संयुक्त

कार्यदल गठित हुआ । 6 नवम्बर 2001 को भारत के प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी और रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुये। सार्क का 11 वां शिखर सम्मेलन 4 से 6 जनवरी 2002 तक काठमाण्डू में सम्पन्न हुआ ।

इसमें कोई दो राय नहीं कि गरीबी और बेरोजगारी भी आतंकवाद का कारण है अतः इन्हें समाप्त करने की दिशा में भारत सहित दुनिया के देशों को कारगर कदम उठाने चाहिए। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासतों जैसे विश्व बन्धुत्व, सौहार्द और भाईचारे दूसरे देषों के साथ कायम करने में पहल करनी होगी। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देशों आपस में बातचीत के द्वारा आपसी विवादों को सुलझाना होगा। और भारत अपने छोटे पडोंसी देशों के साथ नम्र सहायोगी का रूख अपनाना चाहिए। राजनैतिक परिपेक्ष में भाई–भजीजावाद, धर्म के नाम पर राजनीति, अन्याय, भ्रष्टाचार, भेदभाव, पक्षपात को रोका जाना चाहिए। भारत को अपने आंतरिक आतंकवाद पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। भाषा जाति तथा क्षेत्रीय विषमताओं के साथ शासन–प्रशासन को समान व्यवहार करना चाहिए। केन्द्र एवं राज्य सरकारों को आर्थिक विकास और निर्माण कार्यों से रोजगार देने की समुचित व्यवस्थथा करना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण व वोट की राजनीति को शीघ्र समाप्त कर स्वस्थ राजनैतिक वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. त्रिपाठी, मधुसूदन (2008), '' राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद,'' ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. सुंदर, नंदिनी (2011), ''इन्टर्निंग इनसर्जेन्ट पोपूलेशन्स : द बैरीड हिस्ट्रीज ऑफ इण्डियन डेमोक्रेसी,'' इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, फरवरी 5, 2011
3. दत्त रूद्र व के.पी.एम.सुन्द्ररम (2010), '' भारतीय अर्थव्यवस्था,'' एस.चाँद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
4. कुरियन, एन.जे.(2000), '' वाइडनिंग रीजनल डिस्पेरिटीज इन इंडिया,'' इकोनॉमिक एण्ड पॉलीटिकल वीकली, फरवरी 12–18, 2000
5. सिंह,नौनिहाल (1989), '' द वर्ल्ड ऑफ टैररिज्म,'' साउथ एशियन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. मारवाह, वेद(1996), '' पैथोलोजी ऑफ टेररिज्म इन इण्डिया,'' नई दिल्ली।
7. शर्मा, सुरेश के.व.उषा शर्मा (सम्पादक) (1999), '' सोसायटी, इकोनोमी एण्ड कल्चर ऑफ कश्मीर,'' दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
8. खण्डेला, मानचन्द्र (2002), '' अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद,'' आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यटूर्स, जयुपर।
9. लल्लन (2003), ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा,'' सारिका ऑफसेट प्रेस, मेरठ।
10. चन्द्र, महेश व वी.के. पुरी (2005), '' रीजनल प्लानिंग इन इडिया,'' एलाइड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
11. त्रिपाठी, राशि (2010), '' आतंकवाद–मानवाधिकार : चुनौती और समाधान,'' ''बदलते परिदृश्य में नई सहस्राब्दी का भारत,''यादव वीरेन्द्र सिंह (सं), ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
12. यादव, डॉ0 वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) (2010), '' नई सहस्राब्दी का

आतंकवाद–संघर्ष के बदलते प्रतिमान,'' ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

13. यादव, डॉ0 वीरेन्द्र सिह (सम्पादक) (2010), '' बदलते परिदृश्य में नई सहस्राब्दी का भारत,'' ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

Copyright © 2017 *Dr. Umaratan Yadav*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.